FAKT Consult for Management, Training and Technologies
40 Years
Together we can find solutions

कार्यकारी सारांश

परियोजना का **IKI** मध्य-अवधि मूल्यांकन

निम्न-कार्बन और के लिए एकीकृत शहरी जलवायु कार्रवाई **&**

लचीले शहर **(Urban-Act)**

22_I_416_एशिया_जी_अर्बन-एक्ट एकीकृत जलवायु

कार्रवाई

03 मार्च **2026**

परामर्शदाता:

एंड्रिया केरोज़ डी सूज़ा
मारियो डोंगा
श्रीपर्णा सान्याल अय्यर

FAKT GmbH
हैकलैंडरश्ट्रासे **33**
70184 स्टटगार्ट, जर्मनी
info@fakt-consult.de

ठेकेदार:
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH

1 सारांश

1.1 परियोजना का पृष्ठभूमि और मध्य-अवधि मूल्यांकन

परियोजना का संदर्भ और मुख्य उद्देश्य

इस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (आईकेआई) मध्य-अवधि मूल्यांकन (एमटीई) का विषय "**निम्न-कार्बन और लचीले शहरों के लिए एकीकृत शहरी जलवायु कार्रवाई (अर्बन-एक्ट)**" परियोजना है, जिसे डॉयचे गेज़ेलशाफ्ट फर इंटरनेशनले ज़ुसमनारबेट जीएमबीएच (जीआईजेड) और उसके भागीदारों द्वारा पांच देशों (भारत, थाईलैंड, फिलीपींस, चीन और इंडोनेशिया) में लागू किया जा रहा है। यह परियोजना एशिया में तेजी से बढ़ते शहरों के संदर्भ में लागू की गई है, जो बढ़ते जलवायु जोखिमों, चरम मौसम की घटनाओं से बढ़ते नुकसान और हानि, और शहरी बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से मध्यवर्ती शहरों और राष्ट्रीय संस्थानों को शहरी योजना और निवेश प्रक्रियाओं में जलवायु लचीलापन (जलवायु परिवर्तन अनुकूलन), कम-कार्बन विकास (जलवायु परिवर्तन शमन) और सर्कुलर इकोनॉमी (सीई) दृष्टिकोणों को एकीकृत करने में सहायता करके जलवायु-संवेदनशील शहरी विकास को मजबूत करना है।

परियोजना का एक प्रमुख नवाचार बेहतर नीति साधनों, बहु-स्तरीय जलवायु शासन (लंबवत एकीकरण) और जलवायु वित्त तक पहुंच पर इसके संयुक्त ध्यान में निहित है, जिसे कई भागीदार देशों और हितधारकों को शामिल करने वाले एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाता है। इस परियोजना को GIZ के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP), यूनाइटेड सिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स एशिया-पैसिफिक (UCLG ASPAC), स्टटगार्ट विश्वविद्यालय (USTUTT), और टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉर्टमुंड (TUD) के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का कुल बजट 34,625,000 यूरो है, जिसमें फिलीपींस में सीई देश घटक के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा प्रदान की गई 12,000,000 यूरो की सह-फंडिंग शामिल है। फिलीपींस में सह-वित्तपोषित भाग के लिए परियोजना की अवधि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2027 तक है। अन्य घटक सितंबर 2026 तक पहले चरणबद्ध होकर समाप्त हो जाएँगे।

अर्बन-एक्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य अर्बन-एक्ट भागीदार देशों में साक्ष्य-आधारित और समावेशी शहरी जलवायु कार्रवाइयों की योजना और कार्यान्वयन के लिए अनुकूल परिस्थितियों (यानी प्रभावी बहु-स्तरीय जलवायु शासन ढांचे और उपकरण) को बढ़ाना है। यह परियोजना इस उद्देश्य को तीन परस्पर जुड़े स्तरों पर काम करके प्राप्त करने का प्रयास करती है: पायलट शहर, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारें, और क्षेत्रीय स्तर। शहरी स्तर पर, यह परियोजना स्थानिक और विकास योजना में जलवायु परिवर्तन (सीसी) संबंधी विचारों को एकीकृत करने, और जलवायु-संबंधित निवेश परियोजनाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करती है। पायलट अनुप्रयोगों में उत्पन्न साक्ष्य का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, जहाँ नीतियों के साधन, दिशानिर्देश, सेवाएँ और समन्वय तंत्रों में सुधार किया जाता है ताकि शहरों को कम-कार्बन और लचीले शहरी विकास को संबोधित करने में प्रभावी सहायता मिल सके। क्षेत्रीय स्तर पर, यह परियोजना भागीदार देशों और शहरों में, और समग्र रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान, सहकर्मी सीखने और अच्छे अभ्यासों के प्रसार को बढ़ावा देती है।

इस एमटीई का उद्देश्य कार्यान्वयन की स्थिति, उद्देश्यों की प्राप्ति और संभावित चुनौतियों के बारे में संचालन-संबंधी जानकारी प्रदान करके, इसमें शामिल सभी हितधारकों के बीच **सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, जवाबदेही बढ़ाना, और बेहतर निर्णय लेने में योगदान करना** है। एमटीई के परिणामों के मुख्य लक्षित उपयोगकर्ता स्वयं परियोजना और उसके भागीदार हैं, जो परियोजना के प्रबंधन और आगे के विकास के लिए इनका उपयोग करते हैं। जर्मन मंत्रालय और ज़ुक्ुन्फ़्ट-उम्वेल्ट-गेज़ेलशाफ्ट जीजीएमबीएच (ZUG) एमटीई के परिणामों का उपयोग ज्ञान प्रबंधन, कार्यक्रम डिजाइन और राजनीतिक संचालन के लिए करते हैं। रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जाएगा और जर्मन संसद तथा इच्छुक जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया जून 2025 में शुरू हुई और मार्च 2026 में इस रिपोर्ट के साथ समाप्त हुई। एमटीई ने मूल्यांकन मानदंडों का आकलन किया: 1) प्रासंगिकता, 2) योजना, संचालन और सुसंगतता, 3) प्रभावशीलता, 4) परिवर्तनकारी प्रभाव और स्थिरता, 5) सुरक्षा उपाय, और 6) आईकेआई के मानक संकेतक। इसमें मूल्यांकन प्रश्नों (ईक्यू), मानदंडों को आवंटित

मूल्यांकन संकेतकों, और एमटीई आरंभिक चरण के दौरान मूल्यांकन हितधारकों द्वारा उठाए गए अतिरिक्त विशिष्ट सीखने के प्रश्नों (एलक्यू) का आकलन शामिल था।

योगदान विश्लेषण का उपयोग करते हुए एक सिद्धांत-आधारित मिश्रित-विधि दृष्टिकोण लागू किया गया। मूल्यांकन में उपायों के योगदानों का विश्लेषण करने के लिए परियोजना के परिवर्तन के सिद्धांत (ToC) का एक व्यवस्थित आकलन शामिल था। प्रमुख तरीकों में दस्तावेज़ विश्लेषण, ToC संशोधन, सहभागी चिंतन कार्यशालाएं, अर्ध-संरचित साक्षात्कार और सभी संबंधित हितधारक समूहों के साथ फोकस समूह चर्चाएं (FGDs) शामिल थीं। एमटीई टीम के सदस्यों ने भारत, फिलीपींस और थाईलैंड में फील्ड विज़िट किए, जबकि चीन और इंडोनेशिया को दूरस्थ साक्षात्कारों के माध्यम से कवर किया गया। पायलट शहरों में ऑन-साइट विज़िट ने परियोजना कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान की। इस दृष्टिकोण ने व्यापक डेटा संग्रह और विश्लेषण को सुनिश्चित किया, हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया और परियोजना के जटिल संदर्भ में कारण-और-प्रभाव संबंधों के विश्वसनीय मूल्यांकन को सुगम बनाया।

1.2 मूल्यांकन मानदंड के अनुसार मुख्य निष्कर्ष

प्रासंगिकता: यह परियोजना अपने विषयगत फोकस में **अत्यधिक प्रासंगिक** है, विशेष रूप से तेजी से बढ़ रहे एशियाई शहरों में बढ़ते जोखिमों और नुकसान के मद्देनज़र शहरी जलवायु लचीलेपन के संबंध में। संबोधित किए गए विषय, दृष्टिकोण और उपकरण—जैसे कि जलवायु जोखिम-सूचित योजना, प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) और वित्त तक पहुंच—सीधे शहरों और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली **मुख्य चुनौतियों का जवाब देते हैं** और उनकी जरूरतों को संबोधित करते हैं। यह परियोजना राष्ट्रीय रणनीतियों और योजना चक्रों, क्षेत्रीय एजेंडा, और अंतर्राष्ट्रीय ढाँचों, जिनमें पेरिस समझौता, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेन्डाई ढांचा और नई शहरी एजेंडा (NUA) शामिल हैं, के साथ अच्छी तरह से संरेखित है। परियोजना का विशिष्ट अतिरिक्त मूल्य **ऊर्ध्वाधर एकीकरण** और **बहु-स्तरीय जलवायु शासन** के लिए इसके समर्थन में निहित है, जो मौजूदा पहलों को एक अधिक व्यावहारिक, कार्यान्वयन-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ पूरक करता है। व्यावहारिक रूप से, ऊर्ध्वाधर एकीकरण का अर्थ है स्तरों के बीच फीडबैक लूप बनाना: पायलट शहर वास्तविक दुनिया की बाधाओं और अनुभवों के साथ राष्ट्रीय नीति डिजाइन को सूचित करते हैं, जबकि राष्ट्रीय हितधारक ढांचे, मानकों और वित्तपोषण तंत्र को समायोजित करते हैं ताकि स्थानीय कार्यान्वयन को बेहतर ढंग से सक्षम बनाया जा सके। इसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रणनीतियों और स्थानीय कार्यान्वयन की वास्तविकताओं के बीच सामान्य असंबद्धता को कम करना है, जिससे कम-कार्बन और लचीला शहरी विकास अधिक व्यवहार्य और स्केलेबल हो सके। बहु-स्तरीय जलवायु शासन से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे शहरों में जलवायु कार्रवाई को विभिन्न शासन स्तरों और हितधारक समूहों में आकार दिया जाता है, समन्वित किया जाता है और लागू किया जाता है—न केवल राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच ऊर्ध्वाधर रूप से, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों के बीच क्षैतिज रूप से भी। बहु-स्तरीय जलवायु शासन यह स्वीकार करता है कि शहरी जलवायु कार्रवाई किसी एक हितधारक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय और नगर सरकारों, प्रांतीय या क्षेत्रीय प्राधिकरणों, और परिवहन, आवास, पर्यावरण और वित्त जैसे क्षेत्रीय हितधारकों पर निर्भर करती है। इसमें विभिन्न स्तरों पर नीतियों, योजनाओं और उपकरणों को संरेखित करना, संस्थानों और क्षेत्रों के बीच समन्वय में सुधार करना, और भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना शामिल है। इस दृष्टिकोण को विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रासंगिक के रूप में सराहा जाता है। क्षेत्रीय स्तर की भागीदारी, जो मुख्य रूप से कंसोर्टियम भागीदारों ESCAP और UCLG ASPAC द्वारा संचालित है, को क्षेत्रीय पहुंच के लिए प्रासंगिक माना जाता है।

परियोजना योजना, संचालन और सुसंगति: परियोजना योजना, संचालन और सुसंगति को **समग्र रूप से अच्छा** आंका गया है। योजना में ताकत में एक व्यापक और लचीला डिजाइन शामिल है जो देश-विशिष्ट जरूरतों और संदर्भों के अनुकूल अनुकूलन की अनुमति देता है, और वित्त तक पहुंच पर एक अभिनव ध्यान केंद्रित करता है। भाग लेने वाले देशों में, अर्बन-एक्ट योजना राष्ट्रीय ढाँचों और शहर-स्तरीय योजना चक्रों के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है, जिसने समन्वय को सुगम बनाया और यह सुनिश्चित किया कि परियोजना वास्तविक नीतिगत अवसरों का लाभ उठाए। योजना की सीमाओं में बेहतर राष्ट्रीय ढाँचों और पायलट शहर के अनुभवों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के तरीके का अपर्याप्त अनुमान शामिल है। विशेष रूप से, स्थानीय कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए व्यवस्थित क्षमता विकास और इसे राष्ट्रीय एजेंसियों के भीतर शामिल करने के महत्व को कम आंका गया था। इसके अलावा, परियोजना डिजाइन में इस तरह के जटिल सहयोगी माहौल और परियोजना सेट-अप में कार्यान्वयन और क्षेत्रीय सीखने के लिए आवश्यक समय का कम आकलन किया गया प्रतीत होता है। परियोजना संचालन आम तौर पर अच्छा है। एक परिणाम-आधारित निगरानी प्रणाली

मौजूद है, और आंतरिक संचालन संरचनाएं कार्यात्मक हैं। हालांकि, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर भागीदारों के साथ संचालन संस्थागत संचालन संरचनाओं की कमी से प्रतिबंधित है, जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समन्वय को सीमित करता है। समग्र सहयोग प्रबंधन अच्छी तरह से काम करता है, भले ही सहयोग का परिदृश्य अत्यधिक खंडित और जटिल है। हितधारक परियोजना की "क्षेत्रीय अलगाव को तोड़ने" की क्षमता की सराहना करते हैं, जो बहु-स्तरीय जलवायु शासन के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है। परियोजना सक्रिय रूप से और सफलतापूर्वक विभिन्न हितधारकों, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलें भी शामिल हैं, के साथ तालमेल स्थापित करती है।

प्रभावशीलता को भी अच्छा आंका गया है। यह परियोजना समग्र रूप से मजबूत परिणाम तर्क पर आधारित है। यद्यपि कार्यान्वयन मुख्यतः अनुमोदन प्रक्रियाओं में देरी के कारण देर से शुरू हुआ, सभी प्रमुख गतिविधियाँ अब चल रही हैं और कार्यान्वयन में काफी तेजी आई है। प्रारंभिक परिणाम सामने आ रहे हैं। चूंकि आउटपुट प्राप्ति काफी हद तक सही रास्ते पर है, भविष्य में परिणाम प्राप्ति सामान्यतः संभावित प्रतीत होती है। आउटपुट 1 का वर्तमान में ध्यान विभिन्न योजना संबंधी विषयों पर देश-विशेष दिशानिर्देशों को विकसित करने या संशोधित करने पर केंद्रित है। आउटपुट 2 में, पायलट शहर प्रमुख योजना दस्तावेज़ विकसित कर रहे हैं, और आउटपुट 3 में, शहर शहरी जलवायु कार्रवाई निवेश के लिए पूर्व-संभाव्यता अध्ययन निधि के लिए आवेदन करने हेतु परियोजना अवधारणाएं विकसित कर रहे हैं। हालांकि कई प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, परिणाम मिश्रित हैं, जिसमें कई अस्वीकृतियां लेकिन कुछ उल्लेखनीय सफलताएं भी शामिल हैं। इनमें, उदाहरण के लिए, बकोलोड/फिलीपींस का अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना प्रस्ताव शामिल है, जिसे C40 सिटीज़ फाइनेंस फैसिलिटी (CFF) द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है, और इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल (IMT-GT) के छह शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन का प्रस्ताव है जिसे प्री-फैज़िबिलिटी अध्ययन के लिए सिटी क्लाइमेट फाइनेंस गैप फंड (गैप फंड) द्वारा स्वीकार किया गया है। आउटपुट 4 में, एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण श्रृंखला लगभग समाप्त हो चुकी है, जबकि शहरों की प्राथमिकताओं को समझने के बाद, अगस्त 2025 में क्षेत्रीय शहर-से-शहर जोड़ी बनाना शुरू हो गया है, ताकि जोड़ी को रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया जा सके। हालांकि परियोजना के अंत तक परिणाम संकेतक प्राप्त हो सकते हैं, यह अनिश्चित है कि आउटपुट किस हद तक इच्छित परिणामों में परिवर्तित होंगे, विशेष रूप से शहर स्तर पर क्षमता की बाधाओं और भागीदार देशों में सीमित राष्ट्रीय पहुंच रणनीतियों को देखते हुए। विशेष रूप से, यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत नीति उपकरण और संस्थागत प्रशिक्षण की पेशकश किस हद तक साकार होंगे और शहरों द्वारा अपनाए और प्रभावी ढंग से आत्मसात किए जाएंगे।

परिवर्तनकारी प्रभाव और स्थिरता: इस मानदंड को स्वीकार्य के रूप में मूल्यांकित किया गया है, क्योंकि प्रभाव और स्थिरता से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितताएं और जोखिम हैं। वर्तमान कार्यान्वयन स्तर केवल संभाव्यता संबंधी विचारों की अनुमति देता है, क्योंकि प्रभाव अभी उभरना बाकी है। मूल्यांकन टीम का यह मानना काफी हद तक संभावित है कि पायलट शहर के स्तर पर जलवायु-संबंधी प्रभाव और सामाजिक-आर्थिक सह-लाभ प्राप्त होंगे, बशर्ते कि वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके और योजनाओं को लागू किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि परियोजना द्वारा विकसित नीति उपकरण को भागीदार संस्थानों द्वारा नीति उपकरणों के रूप में औपचारिक रूप से मान्य, लागू और अपनाया जाएगा या नहीं। इस बात का जोखिम है कि पहुंच रणनीतियों के अभाव और व्यवस्थित अनुप्रयोग के लिए सीमित क्षमताओं के कारण, शहर की योजनाएं और नीति उपकरण केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह सकते हैं। बड़े पैमाने पर प्रभाव के लिए आवश्यक संरचनात्मक, संस्थागत और व्यवहारिक बदलावों को संबोधित करने के तरीके में कुछ सीमाएँ हैं। हालांकि यह परियोजना संस्थागत सहयोग समझौतों, शुरू की गई निवेश लाइनों, अनुवर्ती पहलों और सुदृढ़ क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से स्थिरता में योगदान करती है, फिर भी सीमित संसाधन और क्षमताएँ—विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के शहरों में—दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करती हैं।

सुरक्षा उपाय और मानक संकेतक: सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को काफी हद तक पर्याप्त रूप से लागू किया गया है। लिंग समानता, विकलांगता और सामाजिक समावेशन (GEDSI) पहलुओं को परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में एकीकृत किया गया है, जिसे एक अध्ययन, फोकल पॉइंट्स और प्रशिक्षण मॉड्यूल द्वारा समर्थित किया गया है। हालांकि, सहभागी तत्व सीमित बने हुए हैं, क्योंकि प्रभावित समूहों को निर्णय लेने में शामिल करने के बजाय मुख्य रूप से सूचित किया जाता है, जो प्रभावशीलता और प्रभाव को सीमित करता है। प्रशिक्षण के माध्यम से समर्थित

लोगों और जुटाई गई वित्त पर मानक संकेतक उपयुक्त हैं और परियोजना की अवधि के भीतर यथार्थवादी रूप से मापे जा सकते हैं। अन्य मानक संकेतकों में योगदान की संभावना केवल दीर्घकाल में ही है।

1.3 मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें

निष्कर्ष: कुछ कमियों के बावजूद निष्कर्षों का समग्र रूप से सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। वे अधिकांशतः अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। एमटीई परियोजना की प्रासंगिकता को उजागर करता है और परिणामों की प्राप्ति के संबंध में सकारात्मक है। कुल मिलाकर, राष्ट्रीय और शहर स्तर पर परियोजना से संतुष्टि का स्तर उच्च है। कथित ताकतें शामिल हैं:

- अवसरों और सही प्रवेश बिंदुओं की पहचान की गई है और उन पर काम किया जा रहा है।
- परियोजना हितधारकों के बीच स्वामित्व का एक स्तर है और दृष्टिकोण बहुत भागीदार-उन्मुख है।
- राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर भागीदारों के साथ उच्च स्तर का विश्वास है
- टीम को समर्पित, लचीला, संवेदनशील और पेशेवर माना जाता है (GIZ और कार्यान्वयन भागीदार)
- सीडी और नई जानकारी तक पहुंच को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। विभिन्न प्रारूपों में बहुत कुछ सीखा जा रहा है।

पहुँच और कार्यान्वयन के संबंध में भी सीमाएँ हैं। प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं:

- परियोजना डिजाइन में कमियाँ, विशेष रूप से पायलट मामलों के विस्तार रणनीति और नीति उपकरणों के लिए पहुंच रणनीति के संबंध में
- पायलट शहरों और कार्यान्वयन भागीदारों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान और संयुक्त सीखने के संबंध में चूके गए अवसर
- विभिन्न देरीयों के परिणामस्वरूप अधिकांश परिणाम अभी भी प्रारंभिक चरणों में हैं और समेकन के लिए बहुत कम समय बचा है
- अब तक, स्थिरता/निकास रणनीति पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है

आगे देखते हुए, परियोजना को शेष परियोजना अवधि का उपयोग परिणामों के समेकन पर ध्यान केंद्रित करने और परिणामों की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आउटपुट / परिणामों की प्राप्ति के उपयोग को सुरक्षित करने के लिए करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों में नीति के रूप में दिशानिर्देश स्थापित करना शामिल है, जइस , जिन्हें भागीदार प्रणालियों द्वारा अपनाया जाता है और जिन्हें सक्रिय रूप से विस्तारित और व्यवहार में लागू किया जाता है।

प्रमुख सिफारिशें
टू अर्बन-एक्ट

- **अमल की तत्परता पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए पायलट शहरों को और अधिक समर्थन दें**: परियोजना प्रबंधन को पायलट शहरों को स्थानिक और विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने में, साथ ही परियोजना अवधारणा नोटों को निधियों के लिए योग्य प्रस्तावों में परिपक्व करने में व्यावहारिक सहायता तेज करनी चाहिए। इस सहायता को स्थानीय तकनीकी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र रूप से उपकरणों, दिशानिर्देशों और योजना दृष्टिकोणों को लागू कर सकें।
- **राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को व्यावहारिक, आवश्यकता-आधारित उपकरणों के रूप में और विकसित करें:** राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को और परिष्कृत किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कार्यान्वयन योग्य, मांग-संचालित और शहरों द्वारा सीधे उपयोग योग्य हों। दिशानिर्देशों को अंतिम उत्पाद मानने के बजाय, उनके विकास को एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया के रूप में डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय और शहर स्तर के बीच ऊर्ध्वाधर सहयोग को सक्रिय रूप से मजबूत करती है।
- **दिशानिर्देश विकास प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण को मजबूत करें:** दिशानिर्देश विकास प्रक्रिया का उपयोग मंत्रालयों और विभागों के बीच ऊर्ध्वाधर एकीकरण (राष्ट्रीय-स्थानीय सहयोग) और क्षैतिज समन्वय में सुधार के लिए रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए।

- **संस्थागत प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा दें:** परियोजना के परिणामों (जैसे दिशानिर्देश, दृष्टिकोण और उपकरण) के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाने चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों के भीतर एक स्पष्ट स्थिरता (निकास) और विस्तार रणनीति के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

आईआईकेआई/ज़ेडयूजी/बीएमयूकेएन को

अर्बन-एक्ट परियोजना के संबंध में:

- **परियोजना की अवधि को लगभग एक अतिरिक्त वर्ष तक, 12/2027 तक बढ़ाने पर विचार करें:** पूर्ण कार्यान्वयन की देर से शुरुआत और अपनाए गए उद्देश्यों की जटिलता को देखते हुए, इस तरह का विस्तार उन परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण समय प्रदान करेगा जो वर्तमान में अभी भी उभर रहे हैं। यह राष्ट्रीय दिशानिर्देशों, पद्धतियों और उपकरणों के अंतिम रूप देने, अनुमोदन और संस्थागत आधार प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय संस्थानों के भीतर प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण दृष्टिकोण को शामिल करने की अनुमति देगा।

प्रस्तावों के लिए आह्वानों के विस्तारीकरण और भविष्य में समान क्षेत्रीय पहलों के डिजाइन के संबंध में:

- ऐसी पहलों को काफी **लंबे समय-सीमा के** साथ, आदर्श रूप से लगभग आठ वर्षों के लिए, सोचा जाना चाहिए और दो चरणों में संरचित किया जाना चाहिए। पहला चरण पायलटिंग, क्षमता विकास और दृष्टिकोणों का परीक्षण करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि दूसरा चरण समेकन, संस्थागतकरण और विस्तार की अनुमति देता है।
- क्षेत्रीय सीखने को मजबूत करने के लिए, मौजूदा **क्षेत्रीय संगठनों और प्लेटफार्मों का** संस्थागत आधार के रूप में व्यवस्थित रूप से **उपयोग किया जाना चाहिए**। ऐसी संरचनाओं में आदान-प्रदान और प्रसार को आधार प्रदान करने से व्यक्तिगत परियोजना चक्रों से परे स्वामित्व, निरंतरता और स्थिरता बढ़ती है।
- **भाग लेने वाले देशों के चयन को** केवल प्रासंगिकता और मांग के आधार पर ही नहीं, बल्कि पूरकता और संभावित राजनीतिक तनावों के बावजूद पारस्परिक सीखने में संलग्न होने की स्पष्ट इच्छा के आधार पर भी किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय आदान-प्रदान तब सबसे प्रभावी होता है जब भागीदार देश विभिन्न शक्तियों और अनुभवों को लाते हैं और एक-दूसरे के साथ साझा करने तथा एक-दूसरे से सीखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।